परिणामी बजट वर्ष 2018–19

विभाग– विधि एवं विधायी कार्य विभाग

विभागाध्यक्ष विधि विभाग एवं विधायी कार्य विभाग

राशि हजार₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2018–19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	विधिक सहायता/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को समानता एवं समान अवसर के आधार पर नि:शुल्क विधिक सहायता दी जाकर शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराना एवं अधिक से अधिक लोगों को विधिक जागरूक बनाना	15000		
		1 विधिक सहायता एवं विधिक सलाह		16000 व्यक्तियों को विधिक सहायता एवं 35000 व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य	
		2 लोक अदालत		1100 लोक अदालत का आयोजन, 55000 प्रकरणों का निराकरण किया जाना	
		3 विधिक साक्षरता/साक्षरता शिविर		9000 शिविरों का आयोजन कर 50 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाना ।	
		4 पेंशन लोक अदालत		180 बैठकों का आयोजन कर 360 प्रकरणों का निराकरण किया जाना ।	